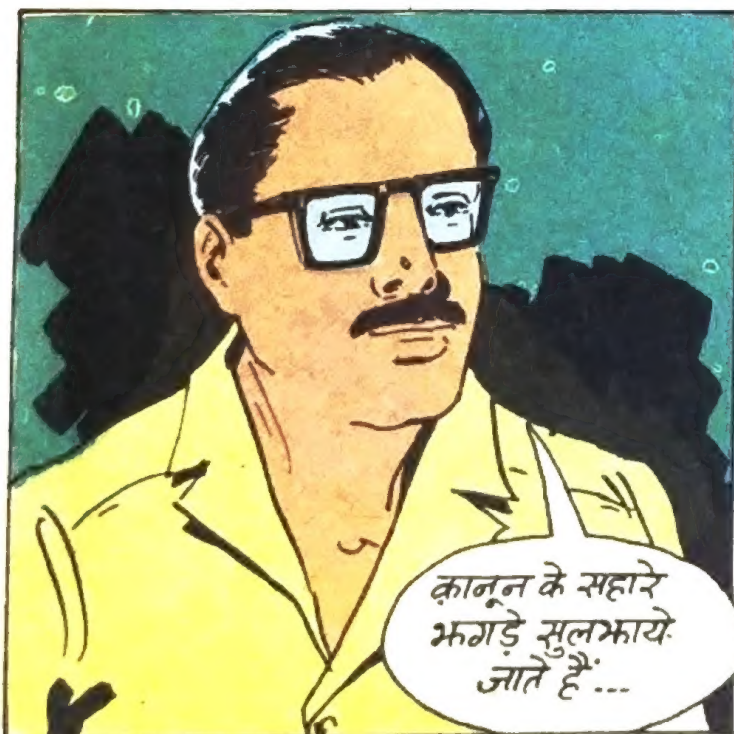


संविधान के सपने



सांविधान के सपने

दिव्या पिछले पांच वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर चुकी थी. जिस समस्या को वह समझती और सुलभाने की कोशिश करती, उसे आभास होता कि कानून की जानकारी बहुत जरूरी है. अब वह शहर के कॉलेज में कानून पढ़ने आई थी. उसका एक विषय था- "नारी और कानून" एक दिन एक गोष्ठी में...











ऐसे हालात समाज सेवी
वकीलों और धात्रों
द्वारा सुधारे जा
सकते हैं।

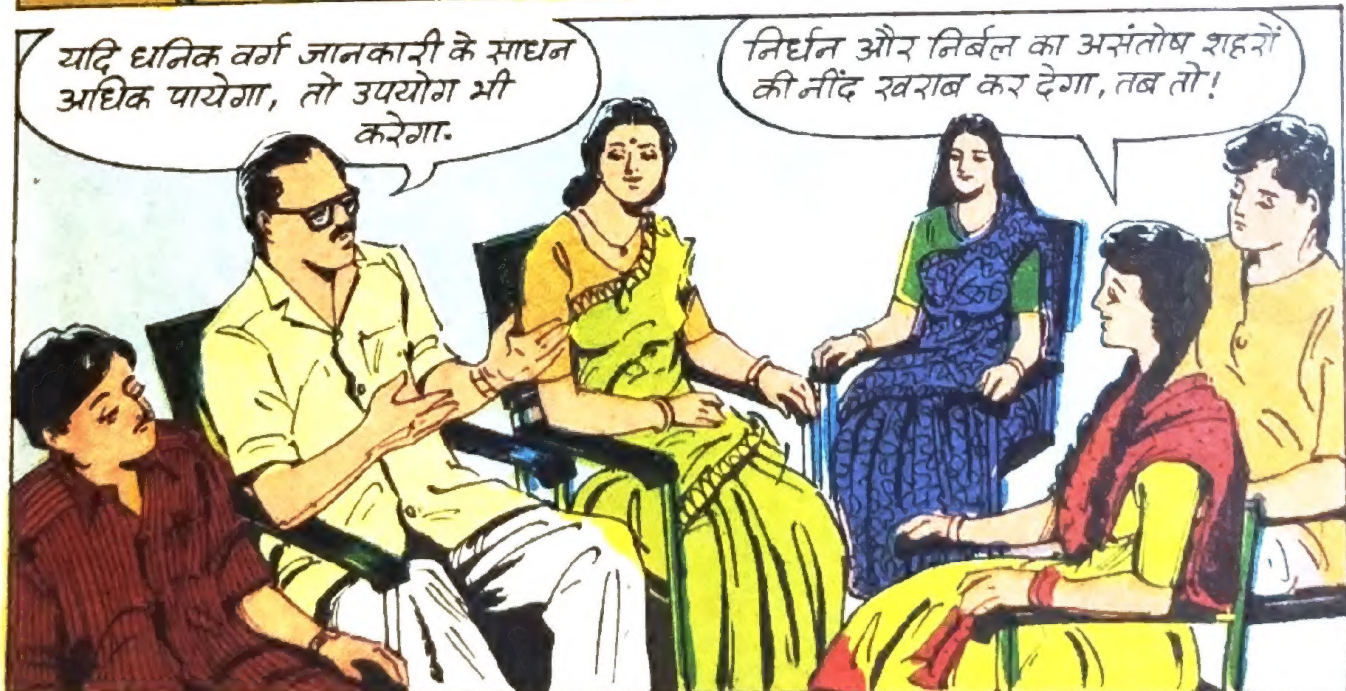
लोक अदालत
एक नई संस्था है।
समय के साथ सुधार
भी होगा।



न्याय की विधियों
को सरल तो
बनाना ही
पड़ेगा।

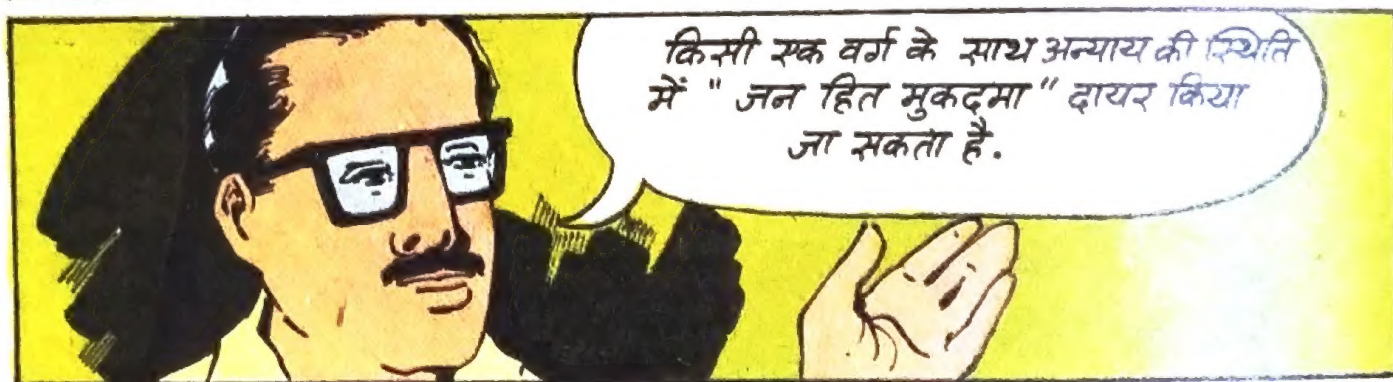


संविधान और कानून
की शक्ति का उपयोग तो
कानून की जानकारी के आधार
पर ही किया जा सकता है।



यदि धनिक वर्ग जानकारी के साधन
अधिक पायेगा, तो उपयोग भी
करेगा।

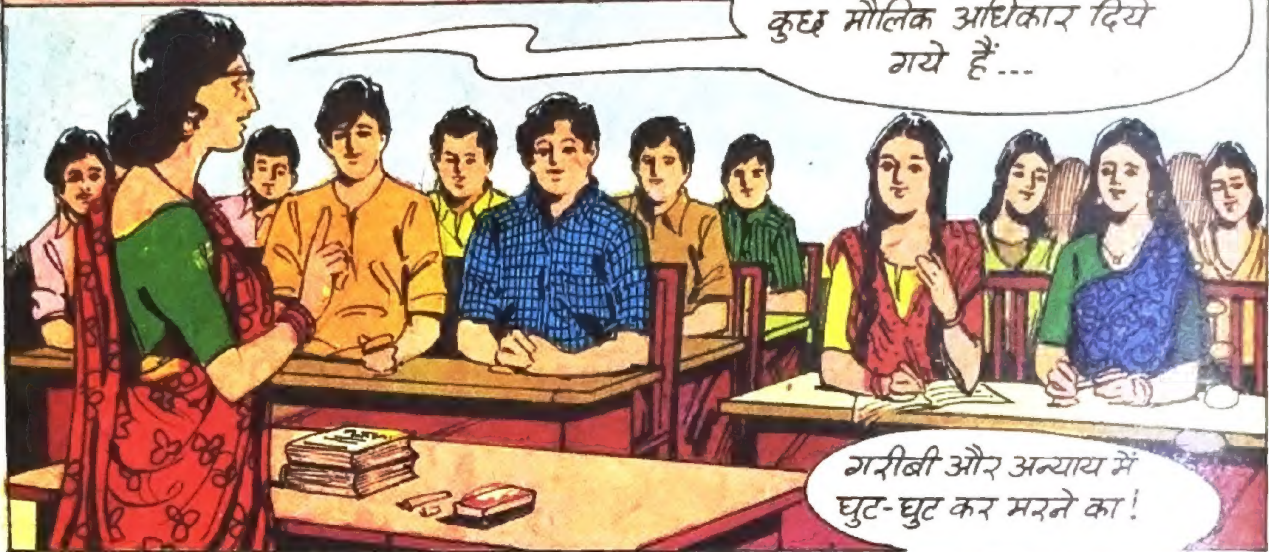
निर्धन और निर्बल का असंतोष शहरों
की नींद खराब कर देगा, तब तो!





"संविधान" विषय पर हो रही एक कक्षा में...

संविधान में हर नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिये गये हैं...



गरीबी और अन्याय में घुट-घुट कर मरने का!

और कुछ निर्देशित सिद्धान्त बताये गये हैं राज्य की नीति के लिये...



जो आज तक पूरे नहीं हो पाये.



मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिये अदालत में जाया जा सकता है.

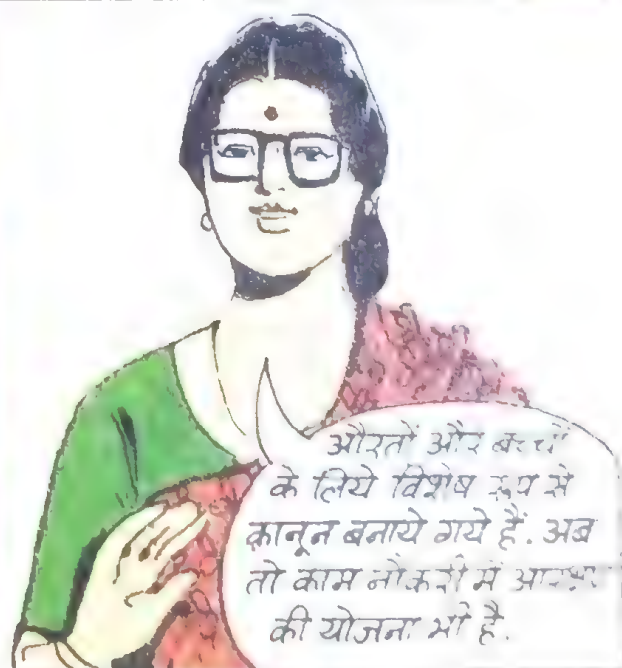
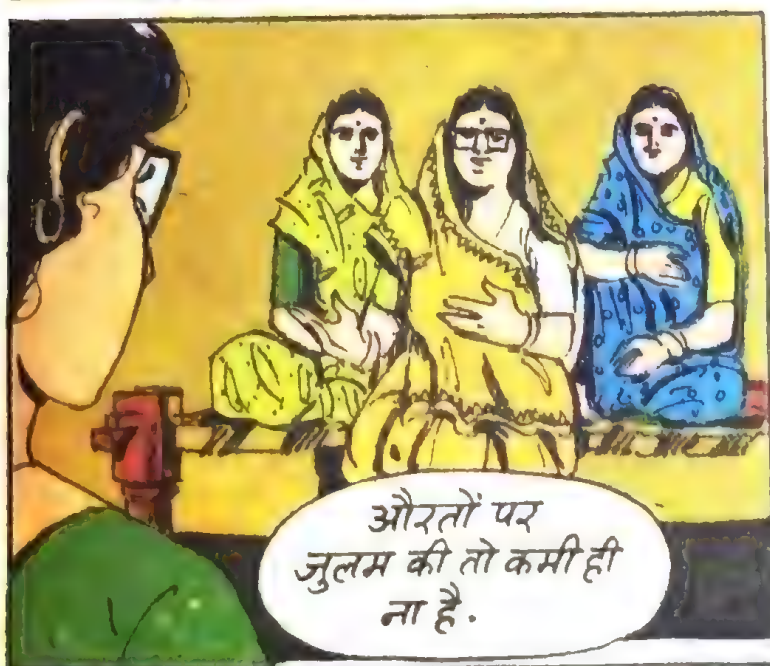
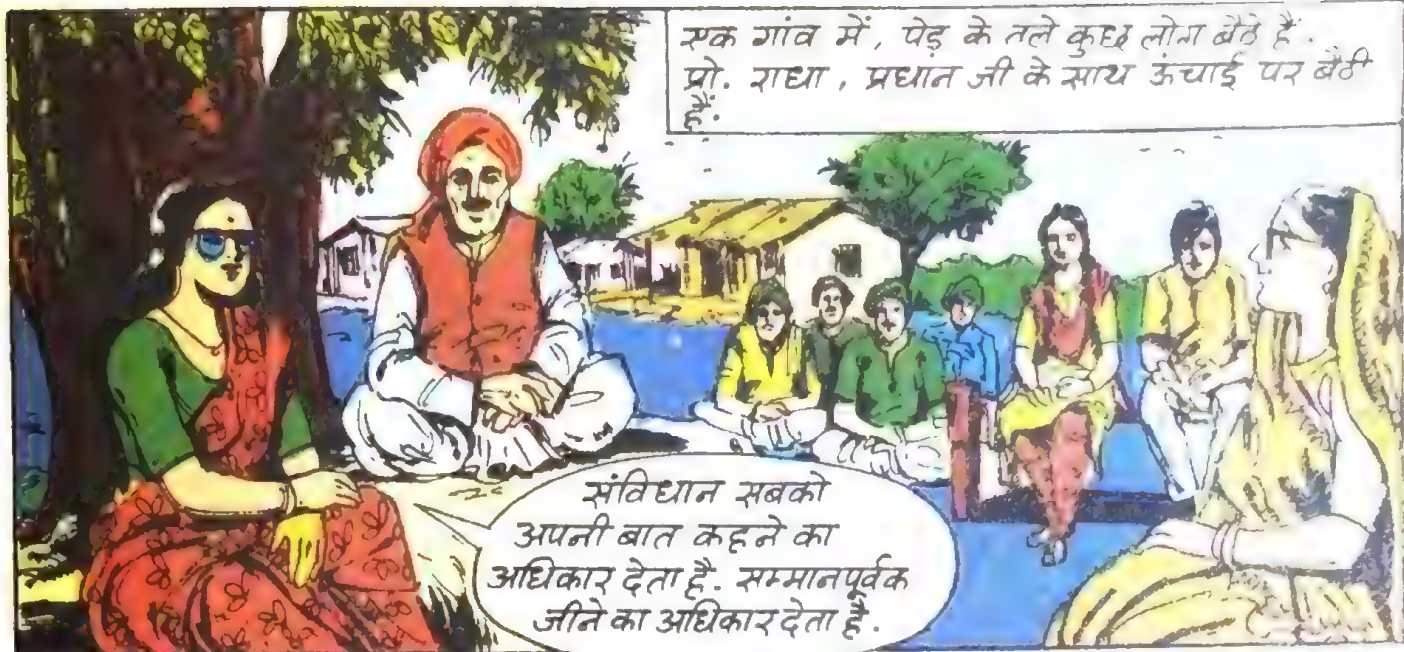


जो कुछ रहा-सहा हो उसे भी लुटाने के लिये.











प्रो. शास्त्री---

संविधान के सपने पूरे करने के लिए तीन साधन हैं: विधान मंडल, प्रशासन तथा न्यायपालिका.

कानून संसद बनाती है, प्रशासन लागू करता है, और न्यायपालिका संविधान और कानूनों का सही अर्थ बताती है.



सर, कानून बनते तो हैं पर न्यायपूर्ण रूप से लागू नहीं किये जाते.

हां. खासकर महिलाओं और बच्चों के कानूनों के बारे में दशा बहुत ही दर्दनाक है.



सर, फिर तो प्रशासन और न्यायपालिका पर संगठित दबाव डालना चाहिये.

पर संगठित दबाव का अर्थ खाली नारे लगाना तो नहीं?



इसके
लिये अन्याय के
तथ्य जमा करें.
कानून की
कमज़ोरियों को
बतायें.



सर, प्रशासन
सब कुछ नहीं बताता.
हर बात को गुप्त रख
कर आम आदमी से
दूर रखता है.



आम आदमी की
नज़र में कानून का अर्थ
पुलिस है. सामाजिक कानूनों
पर पुलिस ने उचित
ध्यान नहीं दिया.



प्रशासन में
भ्रष्टाचार बढ़ रहा
है.



सबसे असरदार
तरीका समाज में जनता की
आवाज़ है. निगरानी और
आक्रोश दोनों ही काम
करते हैं.



सर, दोनों ही
हालात में महिलाओं पर
तो अत्याचार बढ़ते ही
जा रहे हैं.







भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक (संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य) बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए —

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं।